The Hindu 22 February, 2017

# Bond market developing steadily: SEBI official

## Cut in Centre's borrowing plan may help

SPECIAL CORRESPONDENT
KOLKATA

Stressing on the importance of creating an ecosystem that promotes and nurtures the bond market, a SEBI official said here on Tuesday that the reduction in the government's borrowings programme as announced in the Budget augurs well for the bond market.

"This decision has yielded a lot of space to bonds," G. Mahalingam, whole-time member SEBI said, at a conference here. "A broad consensus is emerging on reduced government borrowings and a ₹2 lakh crore gap is there between the ₹5.8 lakh crore borrowing by the earlier government and the ₹3.8 lakh crore budgeted by this government .. this space will be taken over by corporate bonds."

G. Mahalingam

The SEBI member said traditionally in India, government securities had been treated as the only high quality liquid asset (HQLA). "Over a period of time corporate bonds will be treated as HQLA and the amount of bonds being raised is now surpassing bank credit, he said. "The bond market is growing slowly and steadily."

The Telegraph (Kolkata) 22 February, 2017

Sebi whole-time member G. Mahalingam in Calcutta on Tuesday. (PTI)

# Fillip for corporate borrowing

A STAFF REPORTER

**Calcutta, Feb. 21**: Lower government borrowings could augur well for the growth of the corporate debt market, according to capital market regulator Sebi.

The Centre floats bonds as part of its borrowing programme and these government securities dominate the domestic debt market with participation from institutional investors such as banks, mutual funds, insurance companies, pension funds and overseas investors.

With the Centre pledging to cut the fiscal deficit to 3.2 per cent of GDP in 2017-18 and 3 per cent in 2018-19, it has left room for firms to explore debt instruments.

"The government was borrowing around Rs 5.80 lakh crore, just about a couple of years back. Looking at the current budget, the government is looking to borrow just about Rs 3.48 lakh crore. Where does this Rs 2 lakh crore space get filled up? This is where the corporate bond market has to play a very important role," said Sebi whole-time member G. Mahalingam at an Assocham-organised event.

The Sebi member said government securities had been treated as the only high quality liquid asset in the country. "Over a period of time corporate bonds could be treated similarly," he said.

However, unless the secondary market for bonds becomes vibrant, investors will not recognise the importance of these instruments.

A study by Crisil and Ashvin Parekh Advisory Services lists the ratio of bonds to government securities in India at 0.38 per cent, which is lower than countries such as the US (1.6), South Korea (1.42), China (0.47), Singapore (0.73) and Malaysia (0.81).

ASSOCHAM IN THE NEWS

The Financial Express (Kolkata) 22 February, 2017

# 'Lower govt borrowings to help bond market'

The lowering of government borrowings, as announced in the Budget, from ₹5.80 lakh crore to ₹3.48 lakh crore during the current fiscal would augur well for the corporate bond market, a Sebi official said. "The government has expressed its decision to adopt the path of fiscal rectitude. Thus the previous government borrowings figure of ₹5.80 lakh crore has been pared to ₹3.48 lakh crore. This leaves of a gap of more than ₹2 lakh crore," SEBI wholetime member G Mahalingam said at an Assocham seminar in Kolkata on Tuesday. He said this would augur well for the corporate bond market and it could play an important role in plugging the gap.

ASSOCHAM IN THE NEWS

The Times of India (Kolkata) 22 February, 2017

# 'Corp bonds to fill govt borrowing void'

**Kolkata:** With the reduction of government's borrowing programme, the empty space is going to be taken over by the corporate bonds, capital market regulator Sebi's wholetime member Ganesh Mahalingam said on Tuesday.

"As the government is going to be more and more oriented towards fiscal rectitude, we talked a lot about political lack of homogeneity in thoughts, the previous government of UPA left with a fiscal target of 3.2% and this government took over with the same fiscal target in mind. As the government borrowing programme is going to come down, the space is going to be taken over by corporate bonds," he said at a conference on Bond Market organised by Assocham.

According to him, despite all the difference of opinion on political horizon, the good thing that the country needs to celebrate is as far as economic things are concerned, there is a broad consensus emerging.

Business Standard - Hindi (Kolkata) 22 February, 2017

# कम कर्ज लेने से बॉन्ड बाजार को मदद

मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के बाजार से ऋण लेने की राशि 5.80 लाख करोड़ रुपये से घटकर 3.48 लाख करोड़ रुपये करने की बजट में की गई घोषणा से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम ने एसोचैम के एक सेमिनार से इतर कहा, 'सरकार ने राजकोषीय सादगी बरतने का निर्णय लिया है। इस प्रकार सरकार के ऋण की राशि पहले 5.80 लाख करोड़ रुपये रही है जो अब 3.48 लाख करोड़ रुपये रह गई। इसमें करीब दो लाख करोड़ रुपये का अंतर है।' उन्होंने कहा कि इससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मदद मिलेगी और यह इस अंतर को भरने में एक महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। महालिंगम ने कहा कि आम तौर पर भारत में केवल सरकारी प्रतिभूतियों को ही उच्च गुणवत्ता की तरल संपत्ति माना जाता है। लेकिन समय के साथ कॉरपोरेट बॉन्ड को भी ऐसा समझा जाने लगा है और सरकार धीरे-धीरे बॉन्ड बाजार के पक्ष में काम कर रही है। *भाषा*

Naya India 22 February, 2017

# सरकार के कम कर्ज लेने से बांड बाजार को मदद

**कोलकाता, भाषा।** मोजूदा वित्त वर्ष में सरकार के बाजार से रिण लेने की राशि 5.80 लाख करोड़ रुपए से घटकर 3.48 लाख करोड़ रुपए करने की बजट में की गई घोषणा से कारपोरेट बांड बाजार को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम ने यहां एसोचैम के एक सेमिनार से इतर कहा, 'सरकार ने राजकोषीय सादगी बरतने का निर्णय लिया है। इस प्रकार सरकार के रिण की राशि पहले 5.80 लाख करोड़ रुप रही है जो अब 3.48 लाख करोड़ रुपये रह गई। इसमें करीब दो लाख करोड़ रपये का अंतर है। उन्होंने कहा कि इससे कारपोरेट बांड बाजार को मदद मिलेगी और यह इस अंतर को भरने में एक महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। महालिंगम ने कहा कि आम तौर पर भारत में केवल सरकारी प्रतिभूतियों को ही उच्च गुणवत्ता की तरल संपत्ति माना जाता है। लेकिन समय के साथ कारपोरेट बांड को भी ऐसा समझा जाने लगा है और सरकार धीरे-धीरे बांड बाजार के पक्ष में काम कर रही है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Samagya (Kolkata) 22 February, 2017

# सरकार के कम ऋण लेने से बांड बाजार को मदद मिलेगी: सेबी अधिकारी

**कोलकाता** : मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के बाजार से रिण लेने की राशि 5.80 लाख करोड़ रुपये से घटकर 3.48 लाख करोड़ रुपये करने की बजट में की गई घोषणा से कारपोरेट बांड बाजार को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम ने यहां एसोचैम के एक सेमिनार से इतर कहा, 'सरकार ने राजकोषीय सादगी बरतने का निर्णय लिया है। इस प्रकार सरकार के रिण की राशि पहले 5.80 लाख करोड़ रुपये रही है जो अब 3.48 लाख करोड़ रुपये रह गई। इसमें करीब दो लाख करोड़ रुपये का अंतर है।' उन्होंने कहा कि इससे कारपोरेट बांड बाजार को मदद मिलेगी और यह इस अंतर को भरने में एक महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। महालिंगम ने कहा कि आम तौर पर भारत में केवल सरकारी प्रतिभूतियों को ही उच्च गुणवत्ता की तरल संपत्ति माना जाता है।

Virat Vaibhav 22 February, 2017

# विदेशों में स्थित मिशन आयुष, आयुर्वेद का करें प्रचार-प्रसार

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने मंगलवार को कहा कि विदेश में स्थित मिशनों से आयुष और आयुर्वेद जैसे उपचार के वैकल्पिक तरीकों के प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, 'एमईए की तरफ से हमने अपने सारे मिशनों से आयुष और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में संजीदगी से ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास पारंपरिक चिकित्सा के साथ ही वैकल्पिक थैरेपी भी मौजूद हैं और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इन कम खर्चीले उपचार के लिए भारत से काफी उम्मीदे है।' जनरल सिंह ने यहां एसोचेम के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 25 भारतीय मिशनों में आयुष सुविधा केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय वीजा नियमों को सरल बनाने की जरूरत से अवगत हैं और उन्होंने अपने सारे मिशनों को संवेदनशील बनाया है।